भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3050
दिनांक 19.03.2025 को उत्तर देने के लिए

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2024 में 'खनिज से मील के पत्थर' मंडप

3050. श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
श्री खगेन मुर्मु:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आईआईटीएफ 2024 में प्रस्तुत 'खनिज से मील के पत्थर' मंडप के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;
(ख) उक्त मंडप किस प्रकार विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है;
(ग) क्या मंत्रालय ने स्थानीय रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर खनन क्षेत्र में नवाचारों के प्रभाव का कोई आकलन किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2024, नई दिल्ली में खान मंत्रालय के 'मिनरल्स टू माइलस्टोन' पवैलियन का मुख्य उद्देश्य सतत और नवीन खनन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, खनिजों की आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और प्रमुख राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल करने में इनकी महती भूमिका को प्रदर्शित करना है। 'विकसित भारत' 2047 के विजन के लिए खनिज आपूर्ति सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए खनिज

ब्लॉकों के गवेषण, नीलामी और प्रचालन, पुनर्चक्रण, अनुसंधान एवं विकास और कौशल जैसे प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप इनमें से अधिकांश पहलुओं को मंडप में प्रदर्शित किया गया।

(ग) और (घ) पिछले दस वर्षों में खनन क्षेत्र में प्रमुख नवाचारों में खनिज ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीलामी पद्धति की शुरूआत, गवेषण कार्यकलाप को वित्तपोषित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की स्थापना, 50 वर्ष की एक समान पट्टा अवधि और खनन क्षेत्रो के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना शामिल है, जिसमें डीएमएफ जिलों में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को समर्थन देना भी शामिल है। इनमें से कई एसएचजी ने आईआईटीएफ में 8 लाख से अधिक मूल्य के अपने उत्पाद भी प्रस्तुत किए और बेचे। इन नवाचारों से रोजगार में वृद्धि हुई है और आर्थिक विकास में योगदान मिला है। स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर (एससीएमएस) द्वारा किए गए एक अध्ययन, "भारत में खनन क्षेत्र में मानव संसाधन और कौशल आवश्यकता 2019-2025" के अनुसार, वर्ष 2018-19 में खनन क्षेत्र में कुल 117 लाख व्यक्ति रोजगार में थे, और वर्ष 2019-2025 से क्रमागत रोजगार 8.5 लाख रहा। खनन और उत्खनन क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान देता है।

*****